of 30,538 MW for the Eighth Five Year Plan, a capacity of 16,423 MW has been added through various sources.

(b) and (c) As per the preliminary exercises taken by the Government, the capacity addition of 40,226 MW is assessed to be feasible during the period 1997-98 to 2001-02. If this capacity materialises, the all India energy deficit would be only 1.4% by the end of Ninth Five Year Plan. Better Utilisation of existing capacities,, reduction in transmission and distribution losses and better demand management would help to bridge this gap.

निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाएं

71. **श्री बरजिन्दर सिंह हमदर्द** :

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1997 के अंत में देश में अनेक विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन थीं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी परियोजनाएं थीं और उत्पादन तथा संग्रेवण आदि से जुड़ी परियोजनाएं अलग-अलग कितनी थीं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इनमें से अधिकांश परियोजनाएं अपनी मूल समय-सीमा से पिछड़ गयी है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाएं कितनी हैं और उनके निर्माण की मूल लागत कितनी अनुमानित थीं और अब उनके निर्माण पर कितना व्यय होना अपेक्षित है और इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (**श्री रंगराजन कुमारमंगलम**) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Bidding for power contracts

72. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government's attention have been drawn to the news-item captioned "Bidding for power contracts lacks transparency: BHEL" which appeared in Pioneer, New Delhi dated the 3rd April, 1998;

(b)if so, Government's reaction thereto; and

(c)whether his Ministry has taken up the issue with BHEL to ensure level playing field vis-a-vis international equipment suppliers?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARAMANGALAM): (a) Yes Sir.

(b) and (c) Government of India vide their letter dated June 28, 1996 had advised the State Governments that all project which have not yet finalised their EPC contracts should be required to go in for international competitive Biddings (ICBs) in selection of their EPC contracts. The States had been further advised that in case of independent Power Producers (IPPs) which have informed that their EPC contract has been finalised, the State Electricity Boards (SEBs) should satisfy themselves and that it is indeed so and in cases where it is not finalised, the SEBs should ensure that the ICB route adopted is transparent and proper.

No specific complaint has been received from Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) on the violation of ICB norms.

विद्युत उत्पादन में वृद्धि करना

73. **श्री अरिबलेशन दास** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीम योजना के दौरान विद्युत उत्पादन को किस सीमा तक बढाया जायेगा और इस उद्देश्य के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्पादन के वांछित लक्ष्यों में कमी को निजी क्षेत्र की सहायता से पूरा किया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस विषय में अनुसंधान से संबंधित कार्यक्रमों और शुरु किये गये विकास कार्योम के नाम क्या क्या हैं और उनका ब्यौरा क्या है?